Institute of Chinese Studies
ICS Analysis
中国研究所 DELHI
No. 29 March 2015

निर्गमन रणनीतिः चीन को आकर्षित करते भारतीय प्रांत और शहर

अरविंद येलेरी, पीएचडी
एसोसियेट फ़ेलो, चीन अध्ययन संस्थान, दिल्ली
aravind.yelery@gmail.com

भारत और चीन के बीच वर्ष 2001 से व्यापार बढ़ा है, जिसमें आर्थिक कूटनीति ने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने में प्रेरक शक्ति का काम किया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकडों के अनुसार, इन आर्थिक क्रियाकलापों का केंद्र-बिंदु व्यापार ही है (DIPP 2014)। लेकिन व्यापारिक रिश्ते भारत के पक्ष में नहीं हैं और चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे ने भारत के लिए सूक्ष्म-व्यापारिक जटिलताएं पैदा कर दी हैं (जैसे मूल्य कम करना, एसएमई विकास पर प्रतिबंध), जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र में चीनी आयातों पर प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की बाहरी बाधाएं तथा हद से ज़्यादा निर्यातोन्मुखी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि ने चीन को मजबूर किया कि वह अपने औद्योगिक और व्यापारिक ढाँचों के बारे में नया दृष्टिकोण अपनाये। अर्थव्यवस्था को फिर से संतुलित करने के लिए नीतियों में कुछ बदलाव भी किये गये।

चीनी नेतृत्व द्वारा अपनाई गयी उन्हीं नीतियों में से एक 'निर्गमन' (zou chuqu, 走出去) की नीति भी है, जिसका उद्देश्य सामयिक तथा अल्पकालिक व्यापार से आगे क़दम बढ़ाते हुए देश से बाहर औद्योगिक भंडारण का क्रम तैयार करना है, ताकि गतिशील व्यापार और निवेश के द्वारा स्थाई अन्योन्याश्रय का प्रबंध किया जाये।

उभरते हुए बाज़ारों में इस प्रकार के बाहरी निवेशों का उद्देश्य चीनी उद्योगों (सार्वजनिक तथा निजी दोनों) को विदेशी बाज़ारों में बेहतर पहुँच प्रदान कर और चीनी श्रम को निर्यात में उतार-चढ़ाव से बचाते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।

परिणामस्वरूप, भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में परिवर्तन देखने को मिला है। एक तरफ़ जहाँ व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर निवेश ने भी इसे शक्ति प्रदान की है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तालमेल बढ़ा है।

वर्ष 2006 में राज्य परिषद् के चीनी मामलों के विदेशी कार्यालय ने चीन की बाहर जाने की कोशिशों पर केंद्रित चौथे विश्व चीनी मंच का आयोजन किया।

यही नहीं, 'निर्गमन' नीति के अंतर्गत किये जाने वाले चीनी निवेश का इस्तेमाल भारत को यह आश्वासन देने के लिए किया जा रहा है कि व्यापारिक घाटे से संबंधित उसकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है और यह भारत के द्वारा चीनी आयातों को लेकर किये जाने वाले व्यापारिक इलाजों को दरकिनार करने का अप्रत्यक्ष तरीक़ा भी है।

भारत से संबंधित चीन के उप-राष्ट्रीय दृष्टिकोण का संदर्भ

'निर्गमन' रणनीति से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करते समय अक्सर राज्य उद्यमों को 'मार्ग दर्शक' (xianfeng, 先锋) तथा 'हरावल' (kaituozhe, 开拓者) कहा गया (OCAO 2011)। लेकिन केंद्रीकृत SOEs में सख़्त सुधार तथा पुनर्गठन के कारण उप-राष्ट्रीय SOEs को इतनी प्रमुखता इसलिए मिली, क्योंकि स्थानीय सरकारों ने स्थानीय कारोबारों के लिए हितकारी नीतियाँ अपनाईं (Gang and Hope 2013)।

बाहरी देशों में निवेश और व्यापार की संभावनाओं को तलाश करने की चीन की उप-राष्ट्रीय कोशिश को उस नियामक संशोधन से सहायता मिली है, जिससे सरकारी तथा निजी उद्यमों के लिए 'निर्गमन' की नीति संभव हुई। और ये प्रांतीय सरकारें, प्रांतीय SOEs हैं जिन्होंने रणनीति के रूप में इसे प्रभावशाली ढंग से अपनाया है (zhanlue, 战略)। ज़मीनी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के चीन परिषद् (CCPIT) की प्रांतीय परिषदों ने क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के अनुपालन के लिए रणनीतियाँ बनाई हैं।

वृहत् रणनीति के अंतर्गत अपनी गतिविधियों के वैश्वीकरण में भाग लेने हेतु, निजी उद्यमों को भी प्राथमिकता प्रदान की गई है। सरकारी एजेंसियाँ SOEs को यह बताने और समझाने में लगी रहती हैं कि वह इसे अपनायें और इसी प्रकार की एक कोशिश के तहत, वर्ष 2006 में राज्य परिषद् के चीनी मामलों के विदेशी कार्यालय ने चीन की बाहर जाने की कोशिशों पर केंद्रित चौथे विश्व चीनी मंच का आयोजन किया (OCAO 2011)। परिणामस्वरूप , चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सांख्यिकीय रिपोर्ट के

अनुसार, चीन के गैर-वित्तीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में, 2010 तक, SOEs का योगदान (शेयर) 66.2 प्रतिशत रहा (SASAC 2012)।

यही वह राजनीतिक दबाव है जिसके चलते उन आर्थिक उपायों को ढूँढा गया, जिनकी वजह से भारतीय तथा चीनी अर्थव्यस्थाओं के बीच आपसी विचार-विमर्श में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। निवेश तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का चीनी प्रांतों से भारतीय राज्यों तक का दौरा केवल SOEs और स्थानीय सरकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रांतीय निजी उद्यम भी शामिल है।

उप-राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा भारत-चीन संबंधः पूरक गुण

इन सुधार, घटनाक्रम तथा पूरक गुणों को ध्यान में रखा जाये तो, चीन की 'निर्गमन' रणनीति भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की कोशिशों में सहायक है (*IBD* 2015)। दो ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्पादन के अपने संसाधनों तथा बाज़ार के कारकों को दुरुस्त करके, अपने क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रही है। विशेष रूप से, भारतीय राज्य इस समय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

उदारीकरण से पहले संघीय ज़िम्मेदारियों के बँटवारे ने भारत में उप-राष्ट्रीय कारकों की भूमिका को सीमित कर दिया – राज्य निवेशो को प्रभावित नहीं कर सकते, उन्हें विदेशी आर्थिक मामलों पर कोई भी रुख़ अपनाने से रोक दिया गया। 1990 के दशक के प्रारंभ में आर्थिक उदारीकरण ने इन उप-राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित किया कि वह अपने आर्थिक संसाधनों को दुरुस्त करें। उधर चीन में CCPIT ने इस अवधि में, भारतीय राज्य के क़ानूनी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया (CCPIT_EIC 2007)।

> *नये बाज़ारों और उप-राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के संसाधनों ने भारतीय राज्यों को एफडीआई के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है।*

नये बाज़ारों और उप-राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के संसाधनों (भूमि तथा श्रम सहित) ने भारतीय राज्यों को एफडीआई के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है (*FFD* 2014)। इसका सत्यापन अतरी मुखर्जी के अध्ययन से भी होता है, जिसमें बताया गया है कि बाज़ार का आकार, संकुलन के प्रभाव और भारतीय राज्यों में उत्पादन तथा सेवा के आधार के आकार ने एफडीआई प्रवाह पर काफ़ी सकारात्मक असर डाला है, लेकिन इस प्रवाह को जिस चीज़ ने रोका, वह है कराधान तथा श्रम की लागत (Mukherjee 2011:99)। इसीलिए, भारत के उप-राष्ट्रीय तत्व, जो 1990 की दहाई में संघीय सरलीकरण पर हद से ज़्यादा आश्रित थे, उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला।

मौजूदा स्थानीय संसाधनों पर चूँकि दबाव बढ़ रहा था कि वे कम होते राजस्व तथा घटते

पूंजीगत संसाधनों के कारण होने वाले राजकोषीय घाटे को दुरुस्त करें, इसलिए इन उप-राष्ट्रीय कारकों को भारत में राष्ट्रीय नीतिगत सुधारों के अनुरूप सचेत प्रयास करने पर मजबूर होना पडा। इसी प्रकार का एक और उप-राष्ट्रीय पहलू, जिसने भारत को एफडीआई के लिए पसंदीदा स्थान बना दिया (चीन के लिए भी), वह लैंड-यूज़ (भूमि के प्रयोग के) परमिट थे जिन्हें स्थानीय सरकारें निवेश बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकती थीं (*FFD* 2014)। दरअसल, यही वह कारण है जिसकी वजह से चीन द्वारा भारत में किये जाने वाले निवेश उन राज्यों में हो रहे हैं, जहाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लैंड-यूज़ परमिट तथा ऐसे ही दीगर प्रलोभनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

> *चीन द्वारा भारत में किये जाने वाले निवेश उन राज्यों में हो रहे हैं, जहाँ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए लैंड-यूज़ परमिट तथा ऐसे ही दीगर प्रलोभनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।*

अब हालत यह है कि भारत के सभी राज्य, चीन सहित बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए, आपस में गहन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, नव-विभाजित आंध्र प्रदेश निवेशकों को बहुत सी सुविधाएं दे रहा है, जैसे कर-अवकाश, उत्पाद शुल्क में छूट, प्रवेश-कर में रियायत और मुफ़्त ज़मीन (Yinduabc 2014)।

इस प्रकार के अवसर चीनी दिशा-निर्देशकों के पूरक हैं कि मौजूदा बिक्री राजस्व की रक्षा और प्रसार किया जाये तथा बाहरी मुल्कों में बाज़ार का विस्तार किया जाये, प्रतिगामी संयोजन के द्वारा मुनाफ़े के स्तर को बढ़ाया जाये और नये बाज़ार में घुसा जाये। इस प्रकार, भारतीय बाज़ार, और विशेष रूप से, निवेश प्रोत्साहन तथा सरलीकरण के उप-राष्ट्रीय कारक भारत को चीन की उन कंपनियों के लिए लाभप्रद बना रहे हैं, जो निवेश से संबंधित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ यहाँ अधिक समय तक अपनी उपस्थिति को भी सही साबित करना चाहती हैं। अतः, यह एक ऐसा मामला है जहाँ चीन की 'निर्गमन' रणनीति और विकास से संबंधित भारत की उप-राष्ट्रीय ज़रूरत दोनों साथ-साथ चल रही हैं।

चीनी प्रांतो की भारत के साथ व्यवस्था की योजना

इस समय चूँकि बहुत सी आर्थिक संपूरकताएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए चीन की क्षेत्रीय संस्थाओं ने उन्हें पूरा करने के लिए नये तरीक़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, वर्ष 2000 से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि ने भी इसे गति प्रदान की है। चीन के लोगों ने देखा कि भारत की आर्थिक प्रगति चीनी उद्योगों के मुक़ाबले अविरुद्ध है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2000 से 2005 के बीच, नये संयंत्रों और उपकरणों में भारतीय उद्योगों का निवेश चीन के बराबर था। इसी अवधि में, चीन के अंदर जितना एफडीआई आया, उसका आधा एफडीआई भारत में भी आया, जिसने जीडीपी विकास दर को 10

प्रतिशत के आस-पास पहुँचा दिया (Huang 2009)। चीन के लोगों ने सुधारों की तीव्रता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव को देखा, जिसके नतीजे में चीन के उन प्रांतों ने भी अपने पडोसी के साथ भागीदारी की संभावनाओं को तलाश करना शुरू कर दिया जिनकी भारत में पहले कोई उपस्थिति नहीं थी (*CNW* 2014)। इन व्यस्तताओं में व्यापार के साथ निवेश भी शामिल था। दोनों देशों के बीच व्यापार जैसे-जैसे बढ़ रहा है, चीनी प्रांत उसे सुगम बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय उप-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में चीनी निवेश के अवसर अनंत हैं (Yinduabc 2014)।

चीनी प्रांतो की आर्थिक प्राथमिकताएं, उनके भारतीय समकक्षों के साथ विचार-विमर्श की सीमा को तय करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। व्यापारिक उद्देश्यों के तहत, प्रांतीय दल के सचिव तथा अधिकारियों के भारत दौरों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, भारत जाने के रुझान के तहत Yunnan, Jiangxi, Guangxi, Zhejiang और Gansu प्रांतों के पार्टी सचिव ने 2014 में वहाँ जाने वाले व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया (*TOI* 2014; CGIS 2014; CCPIT-GS 2015; CCPIT-SC 2014b; *Guangxi News* 2014)।

प्रांतीय पार्टी सचिव Xia Baolong के नेतृत्व में जाने वाले Zhejiang प्रतिनिधिमंडल ने 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के 11 सहयोग परियोजनाओं तथा ठेकों पर हस्ताक्षर किये (*Livemint* 2014)। इसी तरह, महाराष्ट्र सरकार और Wenzhou नगरपालिका (जो Zhejiang प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत आती है) के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। Wenzhou और महाराष्ट्र के बीच हुए इस सहमति ज्ञापन का मक़सद राज्य में बिजली घर बनाना, बिजली संयंत्र आपूर्ति के उद्योग तथा उपकरण स्थापित करना था (*Trade Fair News* 2014)। इसी तरह, Guangxi स्वायत्त क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर Liuzhou, जो कि एक औद्योगिक केंद्र है, ने एक क़दम और आगे बढ़ाते हुए, Sister City योजना स्थापित करने के लिए इंदौर (मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी) के साथ आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किया (Wang 2009)।

प्रांतीय पार्टी सचिव Xia Baolong के नेतृत्व में जाने वाले Zhejiang प्रतिनिधिमंडल ने 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के 11 सहयोग परियोजनाओं तथा ठेकों पर हस्ताक्षर किये।

इसी तरह से, दिसंबर 2014 में Yunnan की Baoshan नगरपालिका समिति ने कोलकाता और गुवाहाटी का दौरा किया ताकि Yunnan प्रांत तथा भारत के उत्तर-पूर्व और विशिष्ट रूप से, प्रांत-स्त्रीय शहर Baoshan तथा उत्तर-पूर्व भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संपर्कों के अवसर तलाश किये जा सकें। यह उन नई गतिशीलताओं की ओर इशारा करता है, जहाँ चीनी नगरपालिका और प्रांत-स्त्रीय संस्थाएं भारत की किसी भी संघीय इकाई के साथ रिश्ता

क़ायम करने की संभावनाओं को तलाश करती हुई दिखाई दे रही हैं।

> *वर्ष 2009 में, खोदक, भारक तथा अन्य भारी मशीनरी और उपकरणो में दक्ष Guangxi Liugong Group ने मध्य प्रदेश में इंदौर के क़रीब अपनी पहली विदेशी उत्पादन इकाई स्थापित की।*

इन प्रतिनिधि मंडलों और व्यापारिक मेलों के अलावा, Sichuan प्रांत के द्वारा भारत 'पहुँचने' का एक और तरीक़ा अपनाया गया है। हालाँकि, Sichuan भारतीय बाज़ार में चीन के तटीय प्रांतों के मुक़ाबले देर से पहुँचा[1], फिर भी वह भारत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

[1] Sichuan प्रांत 1999 में केंद्रीय सरकार के द्वारा Western Development Strategy (WDS) लागू किये जाने से पहले तक आर्थिक तौर पर महत्त्वहीन था। Sichuan प्रांत की 'going out' रणनीतियों ने केवल उस समय काम करना शुरू किया, जब निजी उद्योग फलने-फूलने लगे और इनके ~~SEOs~~ SOEs को केंद्र की ओर से वित्तीय परियोजनाएं मिलने लगीं। उदाहरण के तौर पर, 1999 से 2008 तक पश्चिमी क्षेत्र को कुल 143 प्रमुख परियोजनाएं मिलीं, जिनमें कुल RMB 2874.2 बिलियन का निवेश किया गया (Lu and Deng 2011: 5)। महत्त्वपूर्ण यातायात गलियारा (ट्रैफिक कोरिडोर) होने तथा उद्योगों के लिए काफी नई संभावनाएं रखने की वजह से Sichuan को इन निवेशों का बडा हिस्सा मिला, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को सँभाल लिया। WDS के पहले 10 वर्षों के अंत में Sichuan का जीडीपी 175 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जो कि 1999 की मात्रा से चार गुना अधिक था (CRI 2010)। ज़ाहिर है, इसकी वजह से 'going out' रणनीति में उसकी रूचि बढ़ने लगी।

Sichuan प्रांत की 'बाहर जाने' की नीति की तुलना तटीय प्रांतों की नीति से करना इसलिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इन प्रांतीय अर्थव्यवस्थाओं के आधार अलग-अलग हैं, इसीलिए देश से बाहर की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए उनके द्वारा भारत को पसंद किया जाना भी पूरी तरह अलग है (CGIG 2015)। फिर भी, जब हम Guangxi प्रांत (जो कि सकल घरेलू उत्पाद तथा चीन के कुल निर्यात में अपनी भागीदारी के मामले में एक कमज़ोर प्रांत है) की रणनीतियों की तुलना भारत के लिए Sichuan की रणनीतियों से करते हैं, तो 'निर्गमन' की तीव्रता का पता लगाना कुछ हद तक आसान हो जाता है।

वर्ष 2009 में, खोदक, भारक तथा अन्य भारी मशीनरी और उपकरणो में दक्ष Guangxi Liugong Group ने मध्य प्रदेश में इंदौर के क़रीब अपनी पहली विदेशी उत्पादन इकाई स्थापित की। असल संयंत्र को स्थापित करने में सात साल लगे, जिसमें से दो साल तो भारत में चार गहन कार्यस्थलों के किये गये दौरों का व्यवहारिक अध्ययन करने में ही लग गये (Peng)। फिलहाल, Liugong भारतीय बाज़ार के 60 प्रतिशत भाग को कवर करता है और उसके पास ग्राहकों की उल्लेखनीय संख्या मौजूद है, मिसाल के तौर पर भारत के शीर्ष दस इंजीनियरिंग ठेकेदारों में से सात ग्राहक Liugong के हैं (Peng 2014)। दूसरी तरफ़, CCPIT Sichuan Council (CCPIT-SC) ने अपने स्थानीय उद्योग को और अधिक एकीकृत माहौल प्रदान करने के लिए 2010 से Chengdu में दक्षिण एशिया आर्थिक

तथा व्यापारिक गोलमेज़ सम्मेलन कराने का एक मॉडल तैयार किया। प्रतिवर्ष होने वाले इस दो-दिवसीय सम्मेलन में चीन में उपस्थित दूतावास तथा वाणिज्य-दूतावास, SAARC देश के अधिकारियों, हर देश के चैंबर ऑफ़ कामर्स के प्रतिनिधियों, और Sichuan के बुनियादी ढाँचे के निर्माण उद्यमियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। जून 2014 में हुई पिछली गोलमेज़ का विषय था "दक्षिण-एशियाई देशों में ढाँचा- निर्माण और प्रगति के नये अवसर" (*Nanya guojia jichu sheshi jianshe yu fazhan xin jiyu* -南亚国家基础设施建设与发展新机遇) (CCPIT-SC 2014a; CCPIT-SC 2014b)।

इसके साथ ही, Sichuan पारंपरिक पैटर्न का भी पालन करता है। उदाहरण के लिए, इसने मध्य प्रदेश में एक विशेष औद्योगिक पार्क बनाने में रूचि दिखाई है। इसमें चीन की वे कंपनियाँ शामिल होंगी, जिनकी रूचि कृषि उद्योगों तथा उद्यमों में है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म ब्यूरो ने, मई 2013 में, Sichuan के अपने भागीदारों के साथ संपत्ति विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जो इस बात का प्रमाण है कि सार्वजनिक गैर-विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र में चीनी भी कैसे अपना भाग्य आज़माने की कोशिश कर रहे हैं (CCPIT-SC 2014c)। इन उप-राष्ट्रीय संस्थाओं में मौजूद संभावनाओं को देखते हुए, Sichuan प्रशासन मध्य प्रदेश को परस्पर सहयोगी-राज्य कार्यक्रम के निर्माण में अपना पसंदीदा भागीदार बनाने पर ग़ौर कर सकता है।

इसी प्रकार, वर्ष 2013 में, Jiangxi प्रांतीय CCPIT Council ने चीन में स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से 'भारत-चीन व्यापार निवेश मंच' का आयोजन कराने में रुचि दिखाई (CCIC-JCC 2013)। चीन के दूसरे प्रांत भी इसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं और भारत के साथ अपनी साझेदारी शुरू करने के लिए प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, Xinjiang Uyghur स्वायत्त क्षेत्र वाणिज्य चैम्बर, Fujian प्रांत, Shanghai नगरपालिका का CCPIT तथा Zhejiang प्रांत के Taizhou जैसे शहर इस प्रकार के प्रोग्राम पहले ही आयोजित कर चुके हैं (CGIS 2014; CGIS 2013; *Xinhua* 2013)।

> *चीनी गुजरात में आधारभूत ढाँचा, भारी मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा, कपडा, भारी इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के इच्छुक हैं।*

चीन का हर एक प्रांतीय CCPIT जहाँ भारतीय राज्यों के साथ पूरकताओं को ढूँढने में लगा हुआ है, वहीं ऐसा लगता है कि गुजरात का प्रोफ़ाइल व्यापार तथा निवेश से संबंधित उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिल्कुल सटीक है। गुजरात को भारत में Guangdong के समकक्ष समझा जाता है, जिसने 1990 की पूरी दहाई में चीनी आर्थिक विकास को बनाये रखा (*Huanqui.com* 2014)। गुजरात की उत्पादक क्षमताओं तथा आधारभूत ढाँचे को देखते हुए, चीनी इस राज्य में निवेश करने तथा इसके साथ साझेदारी करने के लिए

सबसे अच्छी जगह मान रहे हैं। इसीलिए Sichuan, Zhejiang, Guangzhou तथा Shanghai ने गुजरात में निवेश करने का वायदा पहले से ही कर रखा है (*Business Standard* 2015; CCPIT-SC 2015; *Huanqiu.com* 2014)। चीनी गुजरात में आधारभूत ढाँचा, भारी मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा, कपडा, भारी इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के इच्छुक हैं (*Business Line* 2014)।

> *चीन के स्थानीय अभिनेता विभिन्न प्रकार के विशेष उत्पादों द्वारा भारत के छोटे-छोटे बाज़ारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं।*

चीनी प्रांतों द्वारा पर्यटन, बुनियादी ढाँचा, और औद्योगिक उत्पादों में निवेश करने के अलावा कृषि-व्यापार की संभावनाओं को भी तलाश करने की कोशिश की जाती रही है। Sichuan के द्वारा मध्य प्रदेश के साथ समझौता करने के बाद Gansu प्रांतीय CCPIT भारतीय राज्यों के साथ कृषि-सामग्रियों में साझेदारी करने की सोच रहा है (CCPI-GS 2015)। इसी प्रकार, Jiangsu प्रांत ताज़े पानी में मछली-पालन को बढ़ावा देने के 'द्वि-प्रांतीय' परियोजना के लिए पंजाब राज्य के साथ सहयोग बनाने में मदद करेगा (*TOI* 2014)।

यहाँ पर, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रति चीन के दृष्टिकोण का विशेष रूप से हवाला देना दिलचस्प होगा। Baoshan City ने 10 और 15 फ़रवरी 2015 के बीच, असम राज्य द्वारा गुवाहाटी में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बाग़बानी प्रदर्शनी में भाग लिया (*Fairnews* 2015)। Baoshan नगरपालिका का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि चीन के स्थानीय कारक विभिन्न प्रकार के विशेष उत्पादों द्वारा भारत के छोटे-छोटे बाज़ारों को इस्तेमाल करना चाहते है।

इसमें केवल कृषि-उत्पाद ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लाल मांस से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति को अपने हाथ में लेने की Yunnan की रुचि को भी शामिल किया जा सकता है, ख़ास तौर से इसलिए कि चीन को पशुधन उत्पादन, वितरण और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में दक्षता हासिल हो चुकी है (Aubert 2008:5); (Hindu et al. 2013: 181-182)। Yunnan के प्रांतीय और व्यापार प्रतिनिधि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अपने प्रांत के बीच ऐतिहासिक व्यापार-मार्गों का हवाला लगातार देते रहते हैं कि यह व्यापार की संभावनाओं का निकटतम ऐतिहासिक आधार है, जो कि प्रांतीय आर्थिक कूटनीति के स्थानीय औचित्य के अलावा कुछ भी नहीं है।

चीनी स्थानीयकरण भारत में सफल क्यों हो रहा है

तकनीक के क्षेत्र में निवेश तथा विकसित देशों के बाज़ारों के साथ काम करने के अनुभव की वजह से चीनी कंपनियों को चूँकि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल है, इसलिए वे भारत में अपनी कार्यवाहियों के और अधिक अंतर्राष्ट्रीयकरण में

लगी हुई हैं। उनका यह विस्तार तकनीक पर आधारित उनके प्रतिस्पर्धात्मक प्रोफ़ाइल से भी संबंधित है, जिनका महत्त्व मात्र उन्मुख उत्पादन तथा व्यापार से कहीं ज़्यादा भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण में है (Zedtwitz 2005: 138)।

अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के एक कारक के रूप में, घरेलू बाज़ार में तकनीक पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का विश्लेषण करने के अलावा, भारत में अधिक मात्रा में निवेश के दूसरे कारकों का पता लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। 'निर्गमन' रणनीति बनने के बाद सबसे पहले इसे सरकारी संस्थाओं ने अपनाया, फिर निजी संस्थाओं ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि चीनी व्यापारियों को राजनीतिक संस्थानों द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों से इशारे मिलने लगे थे। मिसाल के तौर पर, 2012 की अमरीकी सदन की ख़ुफ़िया समिति ने बाहरी निवेशों में चीन की भूमिका तथा चीन की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अमरीका में निर्गमन की योजना को लागू करने की मंशा का ख़ुलासा किया था (HPSCI 2012)। जहाँ तक चीनी कंपनियों द्वारा अफ़रीक़ी तथा लैटिन अमरिकी (LAC) बाज़ारों पर वर्चस्व की बात है, तो इस मामले में भी यह एक स्थापित सत्य है (CASS 2004)।

कुल मिलाकर, यह झुकाव दिखाता है कि चीनी उप-राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियाँ, अपनी सरकारों से मिलने वाली सहायता सहित, भारत के साथ समानांतर रास्ते बनाने की कोशिश कर रही हैं। बडे स्तर पर, यह दोनों देशों के बीच विदेश नीति के ढाँचे पर उप-राष्ट्रीय कारकों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ताल-मेल बढ़ाने के अद्भुत तरीक़ों की खोज में चीन की हिस्सेदारी ज़्यादा है। इसके नतीजे में, 'निर्गमन' जैसी नई नीतियाँ चीनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होंगी तथा प्रांतीय कारक इनसे विशेष रूप से लाभांवित होंगे। व्यापक पैमाने पर, यह भारत और चीन के बीच नए प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों की शुरूआत है।■

REFERENCES

Aubert Claude. 2008. 'Food Security and consumption Patterns in Chin', *China Perspectives*, No. 2008/5, 5–23.

Business Line. 2014. 'Chinese firms plan industrial parks in Gujarat', 9 June, http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-news/chinese-firms-plan-industrial-parks-in-gujarat/article6099152.ece (accessed on 30 December 2014).

Business Standard. 2015. 'China's industry bodies to sign MoU at Vibrant Gujarat Summit', 5 January, http://www.business-standard.com/article/economy-policy/china-s-industry-bodies-to-sign-mou-at-vibrant-gujarat-summit-115010500589_1.html (accessed on 22 February 2015).

China Chamber of International Commerce Jiangxi Chamber of Commerce (CCIC-JCC). 2013. "Yindu-zhongguo shangye touzi luntan" zai Chang juban' ("印度—中国商业投资论坛"在昌举办) ["India-China Business Investment Forum" held in Nanchang], 29 August, http://www.jxdoftec.gov.cn/tswz/jxmc_1/tpxw/201308/t20130830_289322.htm (accessed on 5 February 2015).

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) - Sichuan Council. 2014a. 'Electronic Monthly Magazine of Sichuan Economic and Trade

Updates', June, http://www.lodzkie.pl/files/biznes/raport_syczuan_06_2014.pdf (accessed on 30 November 2014).

CCPIT- Sichuan Council. 2014b. 'Vice Governor Gan Lin attended the Fifth China (Sichuan) - Trade and economic cooperation in South Asia Roundtable', 6 June, http://www.ccpit-sichuan.org/ccpitsc/Show.aspx?articleId=2954 (accessed on 30 November 2014).

CCPIT- Sichuan Council. 2014c. 'Sichuan Economy and Trade Trends Monthly', December, http://www.ccpit-sichuan.org/ccpitsc/Show.aspx?articleId=2918 (accessed on 30 November 2014).

CCPIT- Sichuan Council. 2015. 'Sichuan guoji shanghui zuzhi qiye canjia 2015 nian Yindu "huoli Gujilate" quanqiu fenghui' (四川国际商会组织企业参加 2015 年印度"活力古吉拉特"全球峰会) [Sichuan International Chamber of Commerce and three enterprises participate in India's "vibrant Gujarat" Global Summit 2015], 1 January, http://www.ccpit-sichuan.org/newshow.aspx?mid=18&id=889 (accessed on 10 February 2015).

China Council for the Promotion of International Trade - Economic Information Department (CCPIT-EIC). 2007. 'Xinxing de yindu: Xin de juese he shiming' (新兴的印度：新的角色和使命) [Emerging India: New roles and missions], March, http://aaa.ccpit.org/Category7/Asset/2007/Jul/24/onlineeditimages/file71185261731689.pdf (accessed on 5 February 2015).

CCPIT- Gansu Council. 2015. 'CCPIT delegation to participate in the twelfth Chinese goods (Mumbai, India) Exhibition', 4 January, http://www.ccpitgs.org/contents/88/10581.html (accessed on 30 November 2014).

Chinese Academy of Social Sciences Study Group (CASS). 2004. 'Cong "zou chuqu" zhanlue gaodu yanjiu lamei shichang kaifa he touzi huanjing' (从'走出去'战略高度研究拉美市场开发和投资环境) [From the "going out" strategy to developing a high-level research on Latin American market openness and investment climate], 26 March, http://qk.cass.cn/ldmzyj/qkml/2004year/3/201009/P020100901571659111586.pdf (accessed on 12 November 2014).

China News Weekly (CNW) 2014. 'Bei zhongguo ren digu de yindu' (被中国人低估的印度) [India underestimated by the Chinese people], 30 October, http://focus.news.163.com/14/1030/11/A9Q58LS100011SM9.html (accessed on 8 February 2015).

China Radio International (CRI). 2010. 'Sichuan Benefits from Ten Years' West Development Strategy', 25 August, http://english.cri.cn/6909/2010/08/25/1721s590988.htm (accessed on 20 February 2015).

Consulate General of India, Guangzhou (CGIG). 2015. 'Sichuan', http://www.cgiguangzhou.gov.in/provinces/province_details/34 (accessed on 20 February 2015).
Department of Industrial Policy & Promotion, MoC, GOI (DIPP). 2014. 'FDI Synopsis on Country – China', http://www.dipp.nic.in/English/Investor/China_Desk/FDI_Synopsis_China.pdf (accessed on 30 November 2014).

Fireinews. 2015. 'Baoshan City participates in the Second Assam International Agricultural Horticultural Exposition', 16 February, http://www.fireinews.com/news-9479164.html (accessed on 18 February 2015).

First Financial Daily (FFD). 2014. 'Yindu "Zhongguo gongye yuanqu" qidai Yin xia ren zongli poti' (印度"中国工业园区"期待印下任总理破题) [India's "Chinese industrial parks" await appointment of new prime minister], 18 March, http://money.163.com/14/0318/07/9NJQ434Q00253B0H.html (accessed on 10 February 2015).

Gang, Fan and Nicholas Hope. 2013. 'The role of state-owned enterprises in China's economy', *US-China 2022*, http://www.chinausfocus.com/2022/china/wp-content/uploads/Part-02-Chapter-16_SC.pdf (accessed on 20 February 2015).

Guangxi News. 2014. 'Peng Qinghua lutuan fangwen Yindu Mengmai he Xin Deli' (彭清华率团访问印度孟买和新德里) [Peng Qinghua leads visit to Mumbai and New Delhi], 2 April, http://www.gxnews.com.cn/staticpages/20140402/newgx533b54a5-10011176.shtml (accessed on 30 November 2014).

Hinh T. Dinh, Thomas G. Rawski, Ali Zafar, Lihong Wang, and Eleonora Mavroeidi. 2013. *Tales from the Development Frontier: How China and Other*

Countries Harness Light Manufacturing to Create Jobs and Prosperity. Washington D.C.: The World Bank.

House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI), US House of Representatives, 112th Congress. 2012. 'Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE', U.S. House of Representatives, 8 October, 1-60, https://intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/documents/Huawei-ZTE%20Investigative%20Report%20%28FINAL%29.pdf

Huanqiu.com. 2014. 'Modi laojia Gujilatebang: Dadan gaige bei shi "Yindu Guangdong"' (莫迪老家古吉拉特邦：大胆改革被视"印度广东") [Modi's home state Gujarat's daring reforms make it "India's Guangdong"], 19 July, http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-09/5140260.html (accessed on 10 March 2015).

Huang Yasheng. 2009. 'Zhongguo yinggai xiqu Yindu shi jingji zengzhang jingyan' (中国应该吸取印度式经济增长经验) [China should learn from India's experience in economic growth], *China Review*. 1 June, http://www.china-review.com/gat.asp?id=21945 (accessed on 3 February 2015).

International Business Daily (IBD). 2015. 'Touzi Yindu, wuda falu fengxian xu fangfan' (投资印度，五大法律风险须防范) [Five fundamental risks to avoid while investing in India,], 12 January, http://intl.ce.cn/sjjj/qy/201501/12/t20150112_4316462.shtml (accessed on 10 February 2015).

Lardy Nicholas. 2014. *Markets over Mao: The Rise of Private Business in China* (Washington: Peterson Institute for International Economics, 2014), pp. 185.

Livemint. 2014. 'Indian, Chinese firms sign MoUs envisaging US$2.5 billion investment', 27 November, http://www.livemint.com/Politics/59jHg4nWPOMXH1i30NcFbI/Indian-Chinese-firms-sign-MoUs-envisaging-25-billion-inve.html (accessed on 30 November 2014).

Lu, Zheng and Xiang Deng. 2011. 'China's Western Development Strategy: Policies, Effects and Prospects', *Munich Personal RePEc Archive* (*MPRA) Paper*, No. 35201, December, p. 5.
Mukherjee Atri. 2011. *Regional Inequality in Foreign Direct Investment Flows to India: The Problem and the Prospects*. Reserve Bank of India Occasional Papers. Vol. 32, No. 2, Monsoon 2011. 99-127.

North East Federation on International Trade (NEFIT). 2015. 'Press Release - A report on visited Economic and Trade Delegation from Baoshan, P. R. China', http://www.nefitindia.com/press.html (accessed on 2 February 2015).

Overseas Chinese Affairs Office of the State Council (OCAO). 2011. '"Zou chuqu" zhanlue gaishu' ('"走出去"战略概述) [The Outline of 'Going Out' Strategy], http://qwgzyj.gqb.gov.cn/yjytt/159/1743.shtml (accessed on 10 February 2015).
Peng Pingping. 2014. 'Zeng Guang anzai Qinghua daxue fabiao yanjiang: Xianjin zhizao qiye guoji hua zhi lu' (曾光安在清华大学发表演讲：先进制造企业国际化之路) [Internationalization Strategy of Advanced Manufacturing Enterprises: A Speech by Zeng Guang at Tsinghua University], 29 December, http://www.liugong.com/about/10224_for_companynews_text.htm (accessed on 8 February 2015).

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC). 2012. 'Guoqi "zou chuqu" yao danhua zhengfu zhanlue' (国企"走出去"要淡化政府战略) ["Going out" of State-owned Enterprises should go beyond following government strategy], http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1271/n20515/n2697175/14789800.html (accessed on 10 February 2015).

Times of India (TOI). 2014. 'China's Jiangsu province to collaborate with Punjab for 'Twin Province' project", 10 November, http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Chinas-Jiangsu-province-to-collaborate-with-Punjab-for-Twin-Province-project/articleshow/45098957.cms (accessed on 5 February 2015).

Trade Fair News. 2014. 'India moves ahead with China-business ties', 12 December, http://tradefairtimes.com/News/China-Business-Ties-dec.aspx (accessed on 30 January 2015).

Wang Yeshe. 2009. 'Guangxi Liuzhou yu Yindu Yinduoer qianshu jianli youhao chengshi yixiangshu' (广西柳州与印度印多尔签署建立友好城市意向书) [Liuzhou and Indore, India sign letter of intent to establish sister-city relationship], 8 July, http://www.gx.chinanews.com/2009/1910_0708/20413.html (accessed on 8 February 2015).

Yinduabc.com. 2014. 'Xianzai shi touzi yindu de zuijia shiji ma' (现在是投资印度的最佳时机吗?) [Is now the best time to invest in India?], 12 Septmber, http://www.yinduabc.com/invest/8737.htm (accessed on 10 February 2015).

Zedtwitz, Maximilian von. 2005. 'International R&D Strategies in Companies from Developing Countries – the Case of China', UNCTAD (ed.), *Globalization of R&D and Developing Countries.* New York: United Nations, 117-140.

The views expressed here are those of the author and not necessarily of the Institute of Chinese Studies.

The ICS is an interdisciplinary research institution which has a leadership role in promoting Chinese and East Asian Studies in India. The *ICS Analysis* aims to provide informed and balanced inputs in policy formulation based on extensive interactions among wide community of scholars, experts, diplomats and military personnel.

ICS ANALYSIS *BACK ISSUES*

No. 38 | Feb 2016	Taiwan's 2016 Elections: Out with the Old Status Quo, In with the New Status Quo
No. 37 | Dec 2015	Violence against Health Personnel in China and India: Symptom of a Deeper Crisis
No. 37 | Dec 2015	चीन और भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसाः एक गहरे संकट का लक्षण
No. 36 | Nov 2015	Studying China
No. 36 | Nov 2015	चीन का अध्ययन
No. 35 | Oct 2015	चीन की वैश्विक आर्थिक रणनीतिः एशिया, भारत और विश्व पर असर
No. 35 | Oct 2015	What does China's Global Economic Strategy mean for Asia, India and the World?

Principal Contributors to ICS Research Funds

Ministry of External Affairs GOVERNMENT OF INDIA

INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH

JAMNALAL BAJAJ FOUNDATION

Institute of Chinese Studies ICS 中国研究所 DELHI

8/17, Sri Ram Road, Delhi - 110054, INDIA
Tel : +91-11-2393 8202 | Fax : +91-11-2383 0728
http://icsin.org | @ics_delhi
facebook.com/icsin.delhi | info@icsin.org